Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 04-07-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 04 July, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	वैश्विक दक्षिण की आवाज़ समकालीन विश्व की प्रगति की कुंजी है: प्रधानमंत्री
Page 03 **Syllabus : Prelims Pointer**	असम में नई गार्सिनिया प्रजाति पाई गई जिसका नाम वनस्पतिशास्त्री की माँ के नाम पर रखा गया
Page 03 **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में फिर से खुला
Page 07 **Syllabus : GS 3 : Environment & Ecology**	प्लास्टिक कचरे में एंडोक्राइन डिसरप्टर: एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा
Page 10 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	क्या सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य द्वारा पारित अधिनियम को रोक सकता है?
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता संविधान की आत्मा हैं

Page 01 : GS 2 : International Relations

घाना की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक संबोधन अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ भारत के कूटनीतिक जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह न केवल अफ्रीकी देशों के साथ भारत के गहरे होते संबंधों को दर्शाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाकर वैश्विक शासन को नया आकार देने के भारत के व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को भी उजागर करता है।

भाषण के मुख्य अंश

1. ग्लोबल साउथ की भूमिका की मान्यता:

- पीएम मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्लोबल साउथ को शामिल किए बिना आधुनिक दुनिया में प्रगति असंभव है।
- उन्होंने विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार का आह्वान किया।

2. ऐतिहासिक सम्मान:

- मोदी को भारत-घाना द्विपक्षीय संबंधों को मान्यता देते हुए घाना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द ऑफिसर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ घाना से सम्मानित किया गया।

3. वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया:

- जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों के रूप में उद्धृत किया गया।
- मोदी ने चेतावनी दी कि औपनिवेशिक युग की कई समस्याएँ अभी भी नए रूपों में मौजूद हैं, जिनके लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता है।

4. वैश्विक शासन सुधार:

- संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में विश्वसनीय सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत की अध्यक्षता में जी-20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मनाया।

Global South's voice key to contemporary world's progress: PM

PM Narendra Modi receives 'The Officer of the Order of the Star of Ghana' from Ghana President John Mahama on Wednesday. ANI

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Progress in the contemporary world will not be possible without giving a voice to the Global South, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday while addressing a joint session of Ghana's Parliament in its capital Accra.

Mr. Modi, who received Ghana's highest state honour 'The Officer of the Order of the Star of Ghana', quoted the country's founding father Kwame Nkrumah, who said that Africa and India are connected by "intrinsic" forces, in a speech outlining the widespread changes sweeping the world and the challenges that persist.

"The world order created after the Second World War is changing fast... The revolution in technology, the rise of the Global South, and the shifting demographics are contributing to its pace and scale. Challenges, such as colonial rule, that humanity has faced in earlier centuries still persist in different forms," Mr. Modi said.

The Prime Minister described the state honour that he received as the "symbol of enduring friendship" between India and Ghana, which has been a priority of India's ties with Africa since the early days of decolonisation in the 1950s.

Governance reforms

"Progress cannot come without giving voice to the Global South," he emphasised, listing "climate change, pandemics, terrorism, and cyber security" as the "new and complex crises" that are posing fresh challenges to the world. "The changing circumstances demand credible and effective reforms in global governance," the Prime Minister said, highlighting the inclusion of the African Union into the G-20.

"We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G-20 during our Presidency," Mr. Modi said.

Uniting forces

Quoting Dr. Nkrumah, Mr. Modi said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." India is a "pillar of strength in the world" that will stand "shoulder to shoulder" with Ghana as it pursues its developmental goals, he vowed.

This is the first speech by an Indian Prime Minister in Ghana's Parliament, with the special meeting being convened by Speaker Alban Kingsford Sumana Bagbin, who had visited India in 2023. Mr. Modi appreciated Ghana's parliamentary system and expressed satisfaction over the formation of the Ghana-India Parliamentary Friendship Society.

5. भारत-अफ्रीका एकजुटता:

- घाना के संस्थापक पिता क्वामे नक्रूमा को उद्धृत करते हुए गहरे ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंधों को रेखांकित किया।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए अफ्रीका के विकास के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की।

6. लोकतंत्र और संसदीय कूटनीति:

- घाना की लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रशंसा की और घाना-भारत संसदीय मैत्री सोसायटी के गठन की सराहना की।

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

1. वैश्विक दक्षिण में भारत का नेतृत्व

- भारत विकासशील विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण की आवाज और नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।
- जैसा कि वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और जी-20 प्रेसीडेंसी जैसे मंचों में देखा गया है, भारत समान प्रतिनिधित्व के साथ एक बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रहा है।

2. उपनिवेशवाद के बाद नैतिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना

- घाना जैसे उपनिवेशवाद के बाद के देशों के साथ भारत की एकजुटता साझा संघर्षों और समान विकासात्मक आकांक्षाओं को उजागर करती है।
  - यह स्वतंत्रता, संप्रभुता और समावेशी विकास के साझा मूल्यों में निहित भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को मजबूत करता है।

3. दक्षिण-दक्षिण सहयोग की प्रासंगिकता

अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग में शामिल हैं:

- आईडीईएएस योजना के तहत ऋण की लाइनें (एलओसी)
- आईटीईसी कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्वास्थ्य पहल
- यह सहयोग पश्चिमी सहायता के लिए एक प्रति-कथा है, जो निर्भरता पर पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देता है।

4. वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता

- वैश्विक संस्थानों की वर्तमान संरचना वैश्विक दक्षिण के हितों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहती है।

- यूएनएससी सुधारों और पुनर्गठित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत का प्रयास कई विकासशील देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

आगे की राह

- **भारत को ये जारी रखना चाहिए:**
  - व्यापार, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा में अफ्रीकी देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।
  - वैश्विक दक्षिण में लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना।
  - वैश्विक शासन वकालत के साथ विकास साझेदारी को रणनीतिक रूप से संरेखित करना।
- विश्व मामलों में वैश्विक दक्षिण प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाने के लिए IBSA, BRICS और G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- घाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और वैश्विक दक्षिण पर उनका जोर बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की आकांक्षापूर्ण नेतृत्व भूमिका को दर्शाता है। समावेशी विकास, लोकतंत्र और सुधार को बढ़ावा देकर, भारत का लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत, समतावादी और बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण करना है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैश्विक दक्षिण के हितों को समायोजित करने के लिए वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार करने में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। भारत ऐसे सुधारों के लिए आम सहमति बनाने में किस हद तक सफल रहा है? (250 Words)

Page : 03 : Prelims Pointer

असम के बक्सा जिले में पेड़ की एक नई प्रजाति, गार्सिनिया कुसुमे की खोज की गई है। इसका नाम वनस्पतिशास्त्री जतिंद्र शर्मा की मां कुसुम देवी के नाम पर रखा गया है। यह उनके द्वारा परिवार के सदस्यों के नाम पर रखा गया चौथा पौधा है।

New *Garcinia* species found in Assam named after botanist's mother

Rahul Karmakar
GUWAHATI

The distinct bloom of *Garcinia kusumae*, a newly identified tree species from Assam.
SPECIAL ARRANGEMENT

Assam has yielded a new-to-science tree species belonging to the genus Garcinia, commonly referred to as *thoikora* in Assamese. The newly described *Garcinia kusumae* has been named in honour of Kusum Devi, the late mother of Jatindra Sarma, one of the authors of the study and the Chairman of Assam's State Expert Appraisal Committee appointed by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

The study, co-authored by Hussain A. Barbhuiya of Mumbai's Bhabha Atomic Research Centre, appears in the latest issue of *Feddes Repertorium*, a peer-reviewed journal focusing on botanical taxonomy and geobotany.

Four in a family

Garcinia kusumae marks the fourth instance of Mr. Sarma naming a botanical discovery after a family member. Previous names include *Amomum pratisthana* (after his daughter), *Syzygium nivae* (wife), and *Garcinia sibeswarii* (father). This is the first time an Indian botanist-researcher has had four plant species named after immediate family members. "The epithet *kusumae*... is in recognition of her enduring support and sacrifices for his [Mr. Sarma's] education," the study noted.

Garcinia, the largest genus in the family *Clusiaceae*, comprises 414 species of shrubs and trees. Pan-tropically distributed, its centres of diversity are found in Africa, Australasia, and Southeast Asia. The genus is known for its floral diversity, frequent presence in lowland tropical rainforests, and considerable pharmacological potential.

33 species

In India, 33 species and seven varieties of *Garcinia* have been documented, with Assam accounting for 12 species and three varieties.

Mr. Sarma found the *thoikora* specimen in Bamunbari, located in Baksa district, in April, during a survey of *Garcinia* species. The tree's distinct morphological features prompted further investigation. Specimens were collected following standard herbarium protocols, including pressing, drying, and preservation.

A dioecious evergreen tree that can grow up to 18 metres tall, *Garcinia kusumae* was observed to flower from February to April, with fruit maturing between May and June.

गार्सिनिया कुसुमे के बारे में

- जीनस: गार्सिनिया (परिवार: क्लूसियासी)
- स्थानीय नाम: थोइकोरा (असमिया में)
- पेड़ का प्रकार: द्विलिंगी, सदाबहार
- ऊंचाई: 18 मीटर तक
- फूल: फरवरी से अप्रैल
- फल: मई से जून
- खोजा गया: बामुनबारी, बक्सा जिला, असम

जीनस - गार्सिनिया का महत्व

- दुनिया भर में कुल प्रजातियाँ: 414
- मुख्य विशेषताएँ:
  - o पैन-ट्रॉपिकल वितरण
  - o समृद्ध पुष्प विविधता
  - o निचले उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है
  - o उच्च औषधीय क्षमता (चिकित्सा, वजन घटाने, आदि में उपयोग की जाती है)

भारत में गार्सिनिया

- प्रलेखित प्रजातियाँ: 33
- किस्में: 7
- असम में: 12 प्रजातियाँ और 3 किस्में

वानस्पतिक योगदान

- जतिंद्र सरमा, अध्यक्ष असम की राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (MoEFCC) ने अब निम्नलिखित नाम रखे हैं:

- o अमोमम प्रतिष्ठाना – बेटी के नाम पर
- o सिज़ीगियम निवे – पत्नी के नाम पर
- o गार्सिनिया सिबेस्वारी – पिता के नाम पर
- o गार्सिनिया कुसुमे – माँ के नाम पर (नवीनतम)

- किसी भी भारतीय वनस्पतिशास्त्री द्वारा चार पौधों की प्रजातियों का नाम अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रखने की पहली घटना।

अध्ययन और प्रकाशन

- हुसैन ए. बरभुइया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के साथ सह-लेखक
- फ़ेडडेस रिपर्टोरियम में प्रकाशित – प्लांट टैक्सोनॉमी पर एक सहकर्मी-समीक्षित पत्रिका

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में खबरों में आए गार्सिनिया कुसुमे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले पर्णपाती वृक्ष की एक नई खोजी गई प्रजाति है।

2. यह क्लूसियासी परिवार से संबंधित है।

3. इस प्रजाति का नाम शोधकर्ता के परिवार के सदस्य के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी।

कौन सा कथन सही है/हैं?

(A) केवल 2

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

Page 06 : GS 2 : Social Justice

भारत का पहला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक, जिसे पहले मित्र क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, 2021 में हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी, समुदाय-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान की और पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा स्टाफ़ और प्रबंधन किया गया।

- यूएसएआईडी से फंडिंग फ़्रीज होने के बाद जनवरी 2025 में संचालन रोक दिया गया।
- अब क्लिनिक को टाटा ट्रस्ट के समर्थन से मई 2025 में "सबरंग क्लिनिक" के रूप में फिर से खोल दिया गया है।

India's first clinic for transgender persons reopens in Hyderabad

Siddharth Kumar Singh
HYDERABAD

Months after India's first transgender persons-led health clinic – Mitr Clinic – was shut down following a funding freeze by USAID, the landmark facility has made a comeback with a new name and renewed financial backing.

Now reopened as Sabrang Clinic, the community-run healthcare centre resumed services in May 2025 with support from the Tata Trusts, project lead Subash Ghosh said. The name Sabrang, meaning 'all colours', signals a more expansive vision for inclusive healthcare.

India's first clinic for transgender people reopened under a new name Sabrang in Hyderabad on Monday. SIDDHANT THAKUR

"Once the USAID issue happened in January, we had to shut down operations. But we reached out to several philanthropic organisations and individuals. And now, Tata Trusts is supporting us," Mr. Ghosh told *The Hindu*.

Launched in 2021 in Hyderabad's Narayanguda, Mitr Clinic broke new ground as the first in India to be entirely staffed and managed by members of the transgender community. "Over 3,000 patients have been served since the clinic started," he said.

विकास का महत्व

1. समावेशी स्वास्थ्य सेवा मील का पत्थर:

- o सार्वभौमिक, समान स्वास्थ्य सेवा पहुँच के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे हाशिए के समुदायों के लिए।

2. समुदाय के नेतृत्व वाला मॉडल:

- o ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को न केवल रोगियों के रूप में बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रशासकों के रूप में सशक्त बनाना प्रणालीगत बहिष्कार को चुनौती देता है।

3. लचीलापन और परोपकार:

- o दानदाता-निर्भर से परोपकार-समर्थित स्वास्थ्य सेवा (टाटा ट्रस्ट के माध्यम से) में परिवर्तन लचीलापन और स्थिरता का एक मॉडल है।

4. नाम में प्रतीकवाद:

- o नया नाम "सबरंग" (सभी रंग) विविधता, गरिमा और समावेश को दर्शाता है - समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित करता है।

भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियाँ

- मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव और कलंक।
- लिंग-सकारात्मक देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी।
- ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर चिकित्सा पेशेवरों का अपर्याप्त प्रशिक्षण।
- किफायती हार्मोन थेरेपी और सर्जरी तक सीमित पहुँच।
- मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पहचान संबंधी दस्तावेज़ संबंधी समस्याएँ।

नीति और कानूनी ढाँचा

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:**
  - o स्वास्थ्य सेवा तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच और लिंग-पुष्टि सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:

- LGBTQIA+ व्यक्तियों को एक कमज़ोर समूह के रूप में मान्यता देता है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आयुष्मान भारत योजना:

- o ट्रांसजेंडर-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पैकेजों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

आगे की राह

- शहरी स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में सबरंग जैसे समुदाय-नेतृत्व वाले क्लीनिकों को संस्थागत बनाना।
- सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर-समावेशी बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षण का निर्माण करना।
- समावेशी स्वास्थ्य मॉडल के वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का विस्तार करना।
- ऐसे क्लीनिकों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सहायता और सामाजिक परामर्श को एकीकृत करना।
- 2019 अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और कलंक को कम करने के लिए जागरूकता अभियान।

निष्कर्ष

- सबरंग के रूप में भारत के पहले ट्रांसजेंडर-नेतृत्व वाले स्वास्थ्य क्लिनिक का पुनरुद्धार केवल फिर से खुलने से कहीं अधिक है - यह गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक वादे की पुष्टि है। यह एक स्केलेबल, समावेशी मॉडल प्रदान करता है जो ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा के लिए नीतिगत इरादे और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। सबरंग क्लिनिक जैसे समुदाय-आधारित मॉडल इन अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं?

Page 07 : GS 3 : Environment & Ecology

लेख में प्लास्टिक कचरे और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरे पर प्रकाश डाला गया है - विशेष रूप से अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायनों (ईडीसी) और भारत और अन्य स्थानों पर प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, दीर्घकालिक बीमारियों और पीढ़ीगत खुशहाली पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Endocrine disruptors in plastic waste: a new public health threat

Plastic pollution is no longer a distant environmental concern; it is a biological invasion with profound implications for human health; infiltration of microplastics and plastic-derived EDCs into human bodies is triggering hormonal disruption, reproductive dysfunction and chronic diseases

Sudheer Kumar Shukla

Plastics have revolutionised modern living with their convenience and affordability, but this same ubiquity is spawning an invisible, long-term health crisis. Beyond choking oceans and clogging landfills, plastics are now infiltrating our bodies through microplastic particles and a cocktail of endocrine-disrupting chemicals (EDCs).

The evidence is clear and deeply concerning: these substances are interfering with our hormonal systems, damaging reproductive health and increasing our susceptibility to chronic diseases, including cancer. India, now the world's largest generator of plastic waste, stands at the epicentre of this escalating public health emergency.

Once considered inert pollutants, microplastics – plastic particles smaller than 5 mm – are now recognised as biologically active. A 2022 study by Vrije Universiteit Amsterdam detected microplastics in the blood of 80% of human participants. Further, a 2024 study published in *Nature Scientific Reports* reported the presence of microplastics in nearly 89% of blood samples in India, with an average concentration of 4.2 particles per millilitre. These particles have also been found in human lungs, hearts, placentas, breast milk, ovarian follicular fluid, and semen. Alarmingly, testicular tissue in Indian men was found to contain three times more microplastics than in dogs.

The plastics in our lives are not chemically neutral. They often contain EDCs such as: Bisphenol A (BPA) and BPS: used in water bottles, food containers, and thermal paper. They also have Phthalates (e.g., DEHP, DBP) that are used to soften plastics and found in cosmetics, toys and IV tubing and PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances), found in food packaging and non-stick cookware.

These chemicals mimic or block natural hormones such as estrogen, testosterone, thyroid hormones, and cortisol. They interfere with receptor binding, disrupt gene expression in reproductive organs, and induce oxidative stress, inflammation, and apoptosis (cell death).

Animal studies published in *Food and Chemical Toxicology* (2023) showed that even low doses of polystyrene microplastics disrupted testosterone levels, impaired sperm production, and damaged the blood-testis barrier. Similar effects were observed in ovaries, where microplastics reduced anti-Müllerian hormone levels, triggered oxidative stress pathways, and induced cell death.

Microplastics in sperm

Recent clinical studies from China and India have linked the presence of microplastics in semen to reduced sperm count, concentration and motility. Exposure to BPA and phthalates has been associated with lower testosterone levels and elevated luteinizing hormone (LH) levels – both indicators of endocrine disruption. A global review published in *Science of the Total Environment* further supports the connection between microplastics and male subfertility. Notably, a 2023 study in *Environmental Science & Technology Letters* reported a strong correlation between microplastic levels in semen and decreased sperm count, motility, and abnormal morphology in Chinese men. In India, studies have documented a 30% decline in average sperm count over the past two decades.

A study published in *Ecotoxicology and Environmental Safety* (2025) found microplastics in 14 out of 18 follicular fluid samples collected from women undergoing fertility treatment in Italy. These particles, along with their associated endocrine-disrupting chemicals (EDCs), were found to compromise egg quality and were linked to menstrual irregularities, reduced estradiol levels, and an increased risk of miscarriage. Epidemiological studies have also linked exposure to phthalates and BPA with conditions such as polycystic ovary syndrome (PCOS), endometriosis, and spontaneous abortions. These associations have been further supported by findings published in *Advances in Pharmacology* (2021) and *Frontiers in Cell and Developmental Biology* (2023).

The International Agency for Research on Cancer (IARC) now classifies several plastic additives as probable human carcinogens.

Case-control studies from India have shown that women with elevated levels of DEHP in their urine face nearly a threefold increased risk of breast cancer (odds ratio = 2.97). Exposure to BPA and phthalates has also been linked to higher incidences of prostate, uterine, and testicular cancers.

In addition to their carcinogenic potential, these EDCs have been implicated in metabolic disorders. By mimicking cortisol, altering insulin sensitivity, and promoting fat storage, EDCs contribute to the development of obesity and type 2 diabetes. Moreover, PFAS exposure has been associated with metabolic syndrome, cardiovascular disease, and thyroid dysfunction, as reported in a 2024 study published in *Frontiers in Public Health*.

Plastic waste in India

India generates over 9.3 million tonnes of plastic waste each year. Of this, approximately 5.8 million tonnes are incinerated, releasing toxic gases, while 3.5 million tonnes end up polluting the environment. Studies have shown that residents in cities like Mumbai are exposed to between 382 and 2,012 microplastic particles daily through air, food, and water. In Nagpur, doctors are reporting an increase in cases of early puberty, respiratory problems, obesity, and learning disorders in children – conditions increasingly linked to plastic pollution. Recent testing by the Central Pollution Control Board (CPCB) detected phthalate concentrations in drinking water samples from Delhi, Jabalpur, and Chennai that exceeded European Union safety limits.

Despite progressive policies like the Plastic Waste Management Rules (2016, updated in 2022 and 2024), enforcement remains inconsistent. Current regulations do not account for low-dose effects or the complex interactions of EDCs, nor do they address the specific vulnerabilities of children and pregnant women.

The health burden associated with EDCs in India is staggering, costing over ₹25,000 crore annually due to increased healthcare spending and lost productivity. The poorest populations, often living near waste dumps or working in the informal recycling sector, bear the brunt of this crisis. Globally, the U.S. reports annual healthcare costs of $250 billion linked to plastic-related chemicals, according to the Endocrine Society.

Biomonitoring and surveillance are crucial for establishing national programmes that measure EDC levels in blood, urine, and breast milk. Longitudinal studies must be funded to assess the health impacts of EDC exposure on fertility, neurodevelopment, and chronic diseases. In addition, public awareness needs to be improved, and behaviour changes should be encouraged, such as educating people on the risks of microwaving food in plastic containers and promoting the use of glass, stainless steel, and EDC-free alternatives. It is also important to advocate for antioxidant-rich diets to help counteract oxidative stress.

Further actions should include enforcing plastic segregation, recycling, and safe disposal, while investing in microplastic filtration systems for water treatment plants. Additionally, incentivising the development of biodegradable, non-toxic materials is essential to reduce EDC exposure.

Plastic pollution is no longer a distant environmental concern; it is a biological invasion with profound implications for human health. The infiltration of microplastics and plastic-derived EDCs into our bodies is triggering hormonal disruption, reproductive dysfunction and chronic diseases.

The science is undeniable, and the time for action is now. For India, the world's most exposed population, this is more than a policy issue – it is a generational imperative. We must address this silent epidemic through science-driven regulation, robust monitoring, education, and systemic change. The health of our people, especially our children, depends on it.

(Dr. Sudheer Kumar Shukla is an environmental scientist and sustainability expert with over 20 years of experience in environmental policy, waste management and the circular economy. He currently serves as head-think tank at Mobius Foundation, New Delhi. sshukla@mobiusf.org)

The poorest populations, often living near waste dumps or working in the informal recycling sector, bear the brunt of the plastic waste crisis. AP

THE GIST

Once considered inert pollutants, microplastics — plastic particles smaller than 5 mm — are now recognised as biologically active. Further, a 2024 study reported the presence of microplastics in nearly 89% of blood samples in India

Animal studies showed that even low doses of polystyrene microplastics disrupted testosterone levels, impaired sperm production, and damaged the blood-testis barrier. Similar effects were observed in ovaries, where microplastics reduced anti-Müllerian hormone levels, triggered oxidative stress pathways, and induced cell death

The health burden associated with EDCs in India is staggering, costing over ₹25,000 crore annually due to increased healthcare spending and lost productivity. This silent epidemic must be addressed through science-driven regulation, robust monitoring, public education, and systemic change

प्रमुख चिंताएँ उठाई गईं:

जैविक रूप से सक्रिय प्रदूषक के रूप में माइक्रोप्लास्टिक:

- माइक्रोप्लास्टिक (<5 मिमी) निम्नलिखित में पाए गए हैं:

- रक्त (भारतीय नमूनों का 89%)
- फेफड़े, प्लेसेंटा, स्तन दूध, डिम्बग्रंथि द्रव और वीर्य
    - अब निष्क्रिय नहीं: वे जैविक रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव, एपोप्टोसिस और सूजन होती है।

प्लास्टिक में एंडोक्राइन डिसऑर्डरिंग केमिकल्स (EDCs):

- **उदाहरण**:
- BPA/BPS – खाद्य कंटेनर, बोतलें
- Phthalates – खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन, IV ट्यूब
- PFAS – नॉन-स्टिक कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग

- ये एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल जैसे हार्मोन की नकल/अवरुद्ध करते हैं, जिसके कारण:
- बांझपन, PCOS, समय से पहले यौवन
- शुक्राणु क्षति, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएँ
- कैंसर, मधुमेह, थायरॉयड विकार

उभरते स्वास्थ्य प्रभाव:

- प्रजनन संबंधी विकार (शुक्राणुओं की संख्या में कमी, अंडे की खराब गुणवत्ता)
- हार्मोनल असंतुलन (एस्ट्रोजन/टेस्टोस्टेरोन व्यवधान)
- कैंसर में वृद्धि (स्तन, प्रोस्टेट, गर्भाशय)
- बच्चों में न्यूरोडेवलपमेंटल और मेटाबॉलिक विकार
- पिछले दो दशकों में भारतीय पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में 30% की गिरावट

भारत-विशिष्ट चुनौतियाँ:

प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक:

- 9.3 मिलियन टन/वर्ष; केवल आंशिक पुनर्चक्रण या भस्मीकरण।
- शहरी गरीबों, कचरा बीनने वालों के लिए जलने, अनियमित जोखिम से उत्पन्न जहरीली गैसें।

पर्यावरण में EDCs:

- भारतीय शहरों (दिल्ली, जबलपुर, चेन्नई) में हवा, भोजन, पानी में पाया गया।
- पीने के पानी में पाया गया, जो यूरोपीय संघ की सुरक्षा सीमा से अधिक है।

नीतिगत कमियाँ:

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016, अद्यतन 2022, 2024) मौजूद हैं, लेकिन:
- प्रवर्तन की कमी
- कम खुराक या संचयी EDC प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया

- कमज़ोर आबादी (गर्भवती महिलाएँ, बच्चे) को ध्यान में नहीं रखा गया

आर्थिक और सामाजिक लागत:

- EDC के कारण भारत का वार्षिक स्वास्थ्य बोझ: ₹25,000 करोड़+
- वैश्विक अनुमान (यू.एस.): $250 बिलियन/वर्ष
- हाशिए पर पड़े लोगों पर असंगत प्रभाव, जो अपशिष्ट स्थलों के पास काम करते हैं

आगे की राह और सिफ़ारिशें:

वैज्ञानिक उपाय:

- रक्त, मूत्र, स्तन के दूध के लिए जैव निगरानी कार्यक्रम
- पीढ़ीगत स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन

सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन:

- प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म करने से बचें
- कांच, स्टील, EDC-मुक्त विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा दें
- ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार को प्रोत्साहित करें

अपशिष्ट प्रबंधन समाधान:

- जल उपचार संयंत्रों में माइक्रोप्लास्टिक निस्पंदन में निवेश करें
- प्लास्टिक पृथक्करण, सुरक्षित पुनर्चक्रण और निपटान लागू करें
- बायोडिग्रेडेबल, गैर-विषाक्त सामग्री नवाचार को प्रोत्साहित करें

नीति अनिवार्यताएँ:

- मौजूदा नियमों को अपडेट करके इसमें शामिल करें:
  - EDC-विशिष्ट विनियमन
  - संचयी जोखिम मूल्यांकन
  - बाल और मातृ भेद्यता प्रावधान
- स्वास्थ्य और पर्यावरण शासन को एकीकृत करें

निष्कर्ष:

- प्लास्टिक कचरा न केवल हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है - यह हमारे जीव विज्ञान में घुसपैठ कर रहा है, हमारे हार्मोन को विकृत कर रहा है, और मानव प्रजनन क्षमता और दीर्घायु को कम कर रहा है। भारत के लिए, जो इस संकट के केंद्र में है, समय की मांग एक विज्ञान-आधारित, बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया है जो स्वास्थ्य, स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता को प्राथमिकता देती है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन (EDC) क्या हैं? उनके स्रोत, प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव और उपभोक्ता उत्पादों में उनकी उपस्थिति को विनियमित करने के लिए आवश्यक रणनीतियों की व्याख्या करें। (250 Words)

Page : 10 : GS 2 : Indian Polity

नंदिनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। सवाल यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2011 के फैसले के बाद लागू किया गया छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 न्यायालय की अवमानना के बराबर है।

Can the Supreme Court halt an Act passed by a State?

What did the Supreme Court mandate in the Nandini Sundar case on July 5, 2011?

R.K. Vij

The story so far:

Disposing of a writ and contempt petition, the Supreme Court in *Nandini Sundar and Ors. versus State of Chhattisgarh* held that the passing of an Act by the State of Chhattisgarh, subsequent to its order, cannot be said to be an act of contempt of the order passed by the Court.

What did SC order of July 2011 state?

The Supreme Court, on July 5, 2011 issued an order stating that the State of Chhattisgarh shall cease and desist from using Special Police Officers (SPOs) in any activities, directly or indirectly, aimed at controlling, countering, mitigating or otherwise eliminating Maoist activities. The Court ordered the State to recall all firearms issued to any of the SPOs. The order said that the State shall take all appropriate measures to prevent the operation of any group, including but not limited to the Salwa Judum and Koya Commandos.

The Court also directed the Union of India to cease and desist from using any of its funds in supporting, directly or indirectly, the recruitment of SPOs for the purposes of engaging in any form of counter-insurgency activities against Maoists. The Court concluded that the appointment of inadequately paid and ill-trained SPOs engaged in checking Maoism was violative of Article 14 and Article 21 of the Constitution.

Why was a contempt case filed?

Consequent to the Supreme Court order of July 2011, the State of Chhattisgarh enacted the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Forces Act, 2011. Section 4(1) of the Act provides that an auxiliary force shall be constituted 'to aid and assist the security forces' in the maintenance of public order and preventing, controlling and combatting Maoist/Naxal violence and insurgency, etc. Section 5(2) of the Act further states that the members of the auxiliary force 'shall not be deployed in the front-line positions of an operation and shall always work under supervision of the security forces...'. The provision of compulsory training for a period not less than six months, is also prescribed under the Act. Only those SPOs, who would be eligible as per these prescribed yardsticks, were to be inducted into the auxiliary force (by screening committee). The legislature thus had addressed all the concerns observed by the Supreme Court.

However, it was argued by the petitioners that the said enactment was not in consonance with the Court's order and therefore amounted to contempt of Court.

Why was contempt prayer rejected?

There were reasons for rejecting the relief sought by petitioners. One, the Supreme Court took cognisance of the fact that all the directions issued by the Court had been complied to by the State of Chhattisgarh and necessary reports were submitted.

Second, the Court said that every State legislature has plenary powers to pass an enactment so long as the said enactment was not declared to be *ultra vires* of the Constitution. Any law made by Parliament or a State Legislature cannot be held as an act of contempt. The Court clarified that a legislature has the power to pass a law, to remove the basis of a judgment or validate a law which has been struck down by a Constitutional Court. This is the core of the doctrine of separation of powers and must always be acknowledged in a constitutional democracy. Any piece of legislation enacted by a legislature can be assailed only on the twin prongs of legislative competence or constitutional validity.

In *Indian Aluminium Co. versus State of Kerala* (1996), the Supreme Court observed that Courts must maintain the delicate balance devised by the Constitution between the three sovereign functionaries. The Court therefore held that unless and until it is first established that the statute so enacted is in opposition to constitutional law or otherwise, it cannot be struck down.

RK Vij is a former IPS officer and views are personal.

THE GIST

- The Supreme Court, on July 5, 2011 issued an order stating that the State of Chhattisgarh shall cease and desist from using Special Police Officers (SPOs) in any activities, directly or indirectly, aimed at controlling, countering, mitigating or otherwise eliminating Maoist activities.
- Consequent to the Supreme Court order of July 2011, the State of Chhattisgarh enacted the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Forces Act, 2011.
- It was argued by the petitioners that the said enactment was not in consonance with the Court's order and therefore amounted to contempt of Court.

सर्वोच्च न्यायालय के 5 जुलाई, 2011 के आदेश में क्या कहा गया था?

- छत्तीसगढ़ राज्य को माओवादी विरोधी अभियानों में सलवा जुडूम और कोया कमांडो जैसे विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का उपयोग बंद करने का आदेश दिया गया था।

एसपीओ की भर्ती और संचालन को असंवैधानिक माना गया, जो निम्न का उल्लंघन करता है:

- o अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता
- o अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
- केंद्र सरकार को उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए एसपीओ को वित्त पोषण बंद करने का निर्देश दिया गया।

इसके बाद राज्य ने क्या किया?

- छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 पारित किया गया।

मुख्य प्रावधान:

o सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और माओवादी हिंसा को नियंत्रित करने में सहायता के लिए एक सहायक पुलिस बल का गठन।
o भर्ती को कम से कम 6 महीने के प्रशिक्षण, स्क्रीनिंग और निरीक्षण के साथ अधिक विनियमित किया जाना था।
o सदस्यों को अग्रिम मोर्चे पर युद्ध में तैनात नहीं किया जाना था।

- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है और उन्होंने अवमानना याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका क्यों खारिज की?

1. पहले के आदेश का पूर्ण अनुपालन:

o राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2011 के निर्देशों का अनुपालन किया था।
o आग्नेयास्त्र वापस ले लिए गए, एसपीओ को निर्देशानुसार भंग कर दिया गया।

2. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत:

o विधानमंडल के पास न्यायालय के निर्णय के बाद भी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है।
o किसी कानून को तब तक "न्यायालय की अवमानना" नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह संविधान का उल्लंघन न करे।
o विधानमंडल न्यायिक निर्णय के आधार को हटा सकता है या निरस्त किए गए कानून को वैध बना सकता है, बशर्ते वह अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहे।

3. न्यायिक समीक्षा अभी भी लागू है:

o ऐसे अधिनियम को विधायी क्षमता या संवैधानिक अमान्यता के लिए चुनौती दी जा सकती है, अवमानना के लिए नहीं।

कानूनी सिद्धांत को मजबूत किया गया:

शक्तियों का पृथक्करण

- न्यायालय कानूनों की व्याख्या करते हैं, विधायिकाएँ कानून बनाती हैं और कार्यपालिकाएँ उन्हें लागू करती हैं।
- न्यायपालिका विधायिका को तब तक कानून बनाने से नहीं रोक सकती जब तक कि वह संविधान का उल्लंघन न करे।

उदाहरण दिया गया:

- **भारतीय एल्युमिनियम कंपनी बनाम केरल राज्य (1996):**
  - न्यायालयों को संविधान के तहत प्रत्येक अंग की कार्यात्मक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए।

शासन और आंतरिक सुरक्षा के लिए निहितार्थ:

- विधायी कार्यों के संबंध में न्यायिक निर्देशों की सीमाओं को स्पष्ट करता है।
- वामपंथी उग्रवाद जैसे जटिल मुद्दों पर विधायी प्रतिक्रिया के लिए लोकतांत्रिक स्थान सुनिश्चित करता है।
- टकराव को नहीं, बल्कि संवैधानिक पाठ्यक्रम सुधार को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष:

- नंदिनी सुंदर अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस विचार को मजबूत करता है कि जब तक संविधान का सम्मान किया जाता है, विधायी क्षमता न्यायिक निर्देश के अधीन नहीं है। इससे संस्थागत संतुलन मजबूत होता है और यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन किए बिना न्यायिक चिंताओं के जवाब में कानून विकसित किए जा सकते हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: क्या कोई विधानमंडल ऐसा कानून बना सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संशोधित या निरस्त कर दे? नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रकाश में चर्चा करें। (250 words)

Page : 08 Editorial Analysis

Socialism, secularism are the spirit of the Constitution

M.A. Baby

is the General Secretary of the Communist Party of India (Marxist)

India's Constitution is not merely a legal document. It is the embodiment of the ideals and the aspirations of a nation that was forged in the crucible of an anti-colonial struggle. Among its most fundamental principles are socialism and secularism, values that are not confined to the Preamble alone but which are woven throughout its text, reflected in the Directive Principles of State Policy, in the Fundamental Rights, and in its very structure. Recent calls by the leadership of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) leadership to remove the words socialism and secularism from the Preamble are not just an attack on semantics but is also a direct assault on the foundational vision of the Indian republic itself.

The RSS General Secretary made this call recently under the garb of criticising the Emergency, which happened 50 years ago, as the words socialism and secularism were added in the Preamble under the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 during the Emergency. It is a deceitful move by the RSS to invoke the Emergency in order to discredit these principles, especially when it colluded with the Indira Gandhi government during that time for its own survival. To use that event in history to now undermine the Constitution reflects the RSS's hypocrisy and opportunism.

Reflected in the Preamble and beyond

Socialism, in the Indian Constitution, is a commitment to social and economic justice, the eradication of inequality, and the creation of a welfare state. The Preamble promises "Justice, social, economic and political" to all citizens, and seeks "Equality of status and of opportunity". It underlines the fact that even before the 42nd Amendment, the spirit of socialism was always present in our Constitution.

There were significant efforts in the Indian Constitution to increase the freedoms of citizens and to reduce the inequalities prevalent in society. The Fundamental Rights were major steps in that direction. Article 14 guarantees equality before law. Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16 ensures equality of opportunity in matters of public employment. These rights, read together with the Preamble and Directive Principles, enshrine a vision of a society free from exploitation, where the dignity of every individual is upheld.

The call to erase 'socialism' and 'secularism' from the Constitution is a calculated move to have an oppressive majoritarian state

The Directive Principles of State Policy have the clearest articulation of the socialist vision, in the Indian Constitution. Articles 38 and 39 clearly lay it out, and is further explained in Articles 41, 42 and 43. These provisions are not just aspirational; they have guided landmark legislation and judicial interpretation in India.

Secularism in the Indian Constitution is not mere religious neutrality but the positive assurance that the state will treat all religions equally, protect the rights of minorities, and ensure that no citizen suffers discrimination on the basis of faith. The original text of the Preamble, even before the addition of the word secular in 1976, had already promised "Liberty of thought, expression, belief, faith and worship" and "Fraternity assuring the dignity of the individual...".

Under Fundamental Rights, Articles 25 to 28 provide the Right to Freedom of Religion and further underscore the secular nature of the Indian Republic. Articles 29 and 30, on Cultural and Educational Rights, too reiterate this. These articles ensure that the state neither identifies with nor privileges any religion, and that every citizen, regardless of faith, enjoys equal rights and protections. Even the Supreme Court of India has repeatedly affirmed that secularism is part of the Constitution's 'basic structure'.

The Basic Structure Doctrine was introduced in 1973 in the Supreme Court's landmark judgment in *Kesavananda Bharati*. It holds that while Parliament can amend the Constitution, it cannot alter its fundamental structure, i.e., the basic structure of the Constitution is inviolable. As mentioned earlier, the 42nd Amendment which introduced the words socialism and secularism in the Preamble of the Constitution was enacted in 1976, three years after this historic verdict. Yet, the additions could be made precisely because they did not violate the basic structure of the Constitution.

Inseparable from the Constitution's fabric

It is a fallacy to claim that socialism and secularism in the Preamble of the Constitution are mere 'additions' or 'impositions' from the 1970s. The Objective Resolution of the Constituent Assembly, the Constituent Assembly debates themselves and the lived experience of India's glorious anti-colonial freedom struggle all testify that these values were central to the vision of the Republic's founders.

The Constitution's commitment to social and economic justice, equality, and fraternity is inherently socialist. Its guarantee of religious liberty, non-discrimination and minority rights is inherently secular. Even if the words socialist and secular (the word secular was there in Article 25(2)(a) even before the 42nd Amendment) were to be removed from the Preamble, the Constitution's core philosophy, structure and provisions would remain unchanged in their essence.

Dr. B.R. Ambedkar's final speech to the Constituent Assembly on November 25, 1949, offers profound insights that reinforce the argument that the notion of equality (which forms the foundation of the ideas of socialism and secularism) is embedded in the Constitution's spirit and structure. B.R. Ambedkar's words remain a guiding light against any attempt to dilute these foundational values.

The real agenda has been exposed

The RSS's demand to remove socialism and secularism from the Preamble of the Constitution is a calculated move to undermine the very foundations of the Indian Republic. It exposes its long-standing agenda to replace the Constitution with a veiled Manusmriti, subvert the secular democratic republic of India, and create a theocratic Hindu Rashtra. The attempt to erase socialism and secularism from the Preamble is an attempt to rewrite history, to delegitimise the legacy of India's anti-colonial freedom struggle, and to pave the way for an oppressive majoritarian state.

The Constitution of India is a living document that is designed to secure justice, liberty, equality, and fraternity for all. Socialism and secularism are the pillars on which the edifice of the Indian Republic stands. To attack them is to attack the very soul of India's democracy. All those who cherish the values of the freedom struggle – a struggle that the RSS was not part of – must stand united in defence of the lofty values of the Constitution, and resist any attempt to destroy the idea of India.

Paper 02 भारतीय राजनीति

UPSC Mains Practice Question: समकालीन भारतीय राजनीति में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या करने में प्रस्तावना की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक जांच करें। (250 words)

संदर्भ :

- आरएसएस नेतृत्व के हालिया बयानों ने इस बात पर राष्ट्रीय बहस को फिर से हवा दे दी है कि क्या आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन (1976) के ज़रिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाया जाना चाहिए। सीपीआई(एम) के महासचिव एमए बेबी इन शब्दों का बचाव करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ़ संविधान में जोड़े गए शब्द नहीं हैं बल्कि संविधान के आधारभूत मूल्यों के प्रतिबिंब हैं।

मुख्य संवैधानिक मूल्य: समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता

1. समाजवाद - अर्थ और संवैधानिक उपस्थिति

संवैधानिक उपस्थिति:

- 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया: "हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं..."
- इसमें मौजूद:

  o राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV) - अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43

  o मौलिक अधिकार जो समानता को बढ़ावा देते हैं - अनुच्छेद 14, 15, 16

दर्शन:

- मार्क्सवादी समाजवाद नहीं, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद - समानता, कल्याणकारी राज्य, पुनर्वितरण और न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) संसाधनों के समान वितरण और धन के संकेन्द्रण को रोकने का आह्वान करते हैं।

समाजवादी मूल्यों से प्रेरित ऐतिहासिक नीतियाँ/कानून:

- ज़मींदारी उन्मूलन
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- मनरेगा, आरटीई अधिनियम
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम

2. धर्मनिरपेक्षता - अर्थ और संवैधानिक उपस्थिति

संवैधानिक उपस्थिति:

- प्रस्तावना (1976 के बाद) "धर्मनिरपेक्ष" चरित्र की पुष्टि करती है।
- अनुच्छेद 25-28: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 29-30: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल:

- धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण नहीं (पश्चिमी मॉडल)
- सभी धर्मों के साथ सकारात्मक राज्य जुड़ाव, जबकि किसी का पक्ष न लेना
- धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा

न्यायिक समर्थन:

- केशवानंद भारती केस (1973) - मूल संरचना का सिद्धांत
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) - धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया

आलोचना और प्रतिवाद: आरएसएस का दृष्टिकोण बनाम संवैधानिक आदर्श

आरएसएस का तर्क:

- आपातकाल के दौरान "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द डाले गए थे, जिन्हें राजनीति से प्रेरित माना जाता है
- तर्क है कि संविधान 1950-1976 तक इन शब्दों के बिना काम करता रहा
- मूल प्रस्तावना को बहाल करने का आह्वान

प्रतिवाद (लेखक का तर्क):

1. आरंभ से ही मौजूद मूल्य:

- शब्दों के बिना भी, उनकी भावना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्निहित थी
- जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव (1946) ने इन आदर्शों की नींव रखी
- धर्मनिरपेक्षता पहले से ही अनुच्छेद 25(2)(ए) में स्पष्ट थी

2. मूल संरचना सिद्धांत:

- समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों को गैर-संशोधनीय मूल मूल्यों के रूप में न्यायिक रूप से बरकरार रखा गया है।
- संविधान के माध्यम से उनका समावेश 42वें संशोधन ने मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया।

3. सामाजिक-ऐतिहासिक संदर्भ:

- ये मूल्य भारत के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, समतावाद और बहुलवाद के दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए हैं।
- अंबेडकर के भाषणों का हवाला देते हुए, लेखक हमें याद दिलाता है कि समानता और न्याय संविधान का नैतिक केंद्र हैं।

मूल संरचना का सिद्धांत और 42वां संशोधन

- केशवानंद भारती मामले (1973) ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के "मूल ढांचे" में बदलाव नहीं कर सकती।
- 42वें संशोधन (1976) ने "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" को जोड़ा - लेकिन ये पहले से ही संविधान के सार का हिस्सा थे।
- इसलिए, ये जोड़ सकारात्मक थे, उल्लंघनकारी नहीं।

राजनीतिक और वैचारिक चिंताएँ

- लेखक ने आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वह निम्नलिखित प्रयास कर रहा है:

  o संवैधानिक इतिहास को फिर से लिखना

  o बहुसंख्यक धर्मतंत्र (हिंदू राष्ट्र) को बढ़ावा देना

  o भारत की बहुलवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करना लोकाचार

- वह समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने को संविधान की समतावादी भावना को मनुस्मृति-आधारित सिद्धांतों से बदलने के बराबर मानते हैं, जिसका अर्थ है जाति पदानुक्रम और बहिष्कार

निष्कर्ष:

- प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने के बारे में बहस केवल शब्दार्थ के बारे में नहीं है; यह संवैधानिक नैतिकता और मूल दृष्टि को चुनौती देने के बारे में है जिसे भारत के संस्थापक पिताओं ने एक बहुलवादी और समतावादी राष्ट्र के लिए निर्धारित किया था। इस तरह के किसी भी कदम को केवल एक संवैधानिक संशोधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत के मूलभूत विचार के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाना चाहिए - एक ऐसा गणतंत्र जो जाति, पंथ या वर्ग की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो।